

सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

साप्ताहिक सूचना पत्र

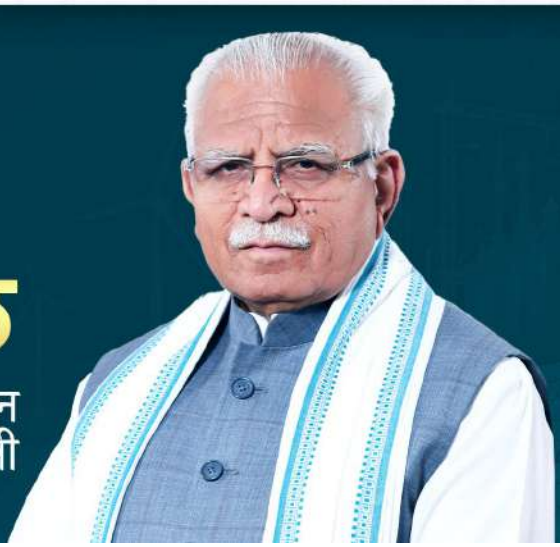
दिनांक 24.10.2026 से 30.10.2026

14वाँ संस्करण



श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय विद्युत तथा आवासन
एवं शहरी कार्य मंत्री



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सत्यमेव जयते

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. 234 गीगावाट की अधिकतम बिजली माँग बिना किसी कमी के पूरी
2. केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह 2026 में भारत का नेतृत्व किया; सिंगापुर, भूटान, IRENA और IEA के साथ द्विपक्षीय वार्ताएँ कीं
3. विद्युत मंत्रालय ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 मनाया; सचिव ने दिलाई सत्यनिष्ठा की शपथ
4. POWERGRID IEC 61850 संस्करण 2.1 सर्वर डिवाइस अनुरूपता परीक्षण मान्यता प्राप्त करने वाली विश्व की पहली यूटिलिटी बनी; 37वाँ स्थापना दिवस मनाया
5. इंडिया एनर्जी स्टैक टास्कफोर्स ने अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की; देशव्यापी क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत
6. REC ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया; AUM में ₹26,537 करोड़ की वृद्धि और नेटवर्थ में साल-दर साल 14% की बढ़ोतरी दर्ज
7. NTPC की सहायक कंपनियों ने BESS और सौर परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की
8. BEE और MSME मंत्रालय ने ADEETIE योजना के क्रियान्वयन को मजबूत करने पर चर्चा की

साप्ताहिक सूचना पत्र

24.10.2026 से 30.10.2026

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

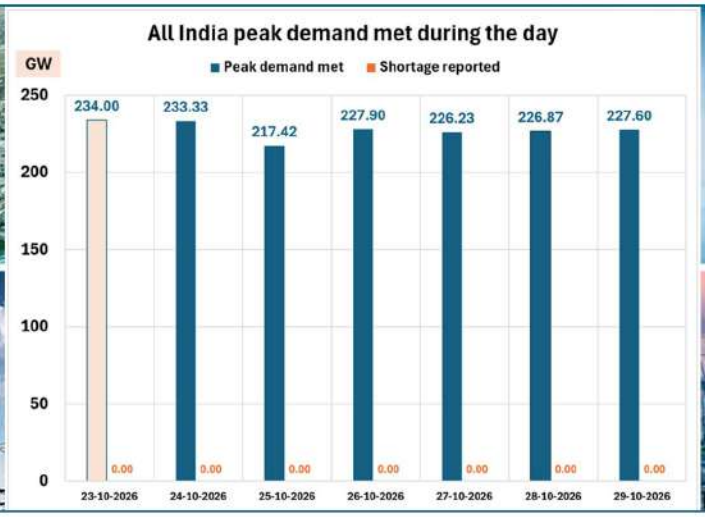
सत्यमेव जयते

29 अक्टूबर 2026

234 गीगावाट की अधिकतम बिजली माँग बिना किसी कमी के पूरी

नीचे दिया गया चार्ट 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन पूरी की गई अधिकतम बिजली मांग और दर्ज की गई बिजली की कमी को दर्शाता है।





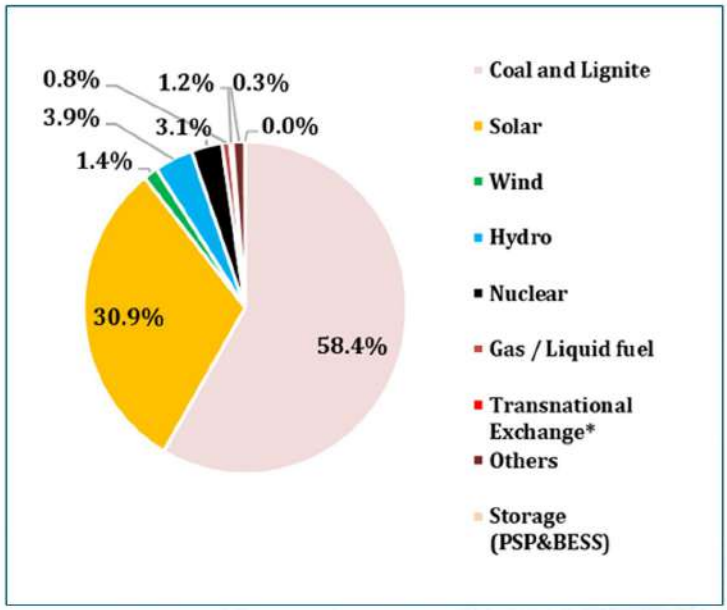






साप्ताहिक अधिकतम मांग के समय कुल विद्युत उत्पादन

Generation source	Generation (GW)	Share of Total generation (%)
Gas / Liquid fuel	1.8	0.8%
Hydro	9.1	3.9%
Nuclear	7.3	3.1%
Coal and Lignite	138.3	58.4%
Wind	3.4	1.4%
Solar	73.1	30.9%
Storage (PSP&BESS)	0.0	0.0%
Others	2.8	1.2%
Transnational Exchange*	0.8	0.3%
TOTAL	236.8	100.0%



23 से 29 अक्टूबर 2026 की अवधि में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, अखिल भारतीय स्तर पर पूरी की गई अधिकतम बिजली मांग और ऊर्जा खपत में क्रमशः 18.0% और 19.4% की वृद्धि दर्ज की गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

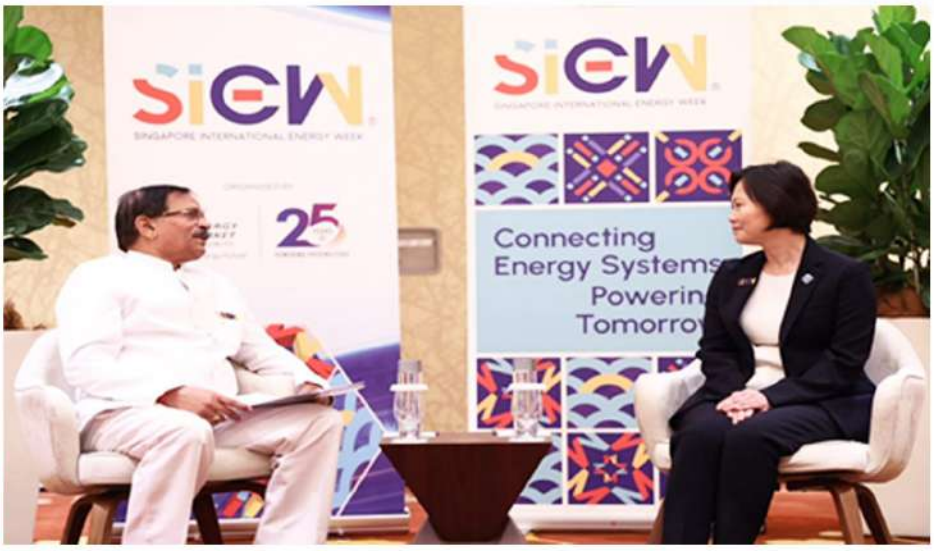
24.10.2026 से 30.10.2026

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

28 अक्टूबर 2026

केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह 2026 में भारत का नेतृत्व किया; सिंगापुर, भूटान, IRENA और IEA के साथ द्विपक्षीय वार्ताएँ कीं





केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक मरीना बे सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह (SIEW) 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने पहले दिन मुख्य वक्तव्य दिया और दूसरे दिन उद्घाटन संबोधन किया।

श्री नाइक ने बताया कि 30 सितंबर 2026 तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 558.9 गीगावाट थी, जिसमें से लगभग 308 गीगावाट यानी 55 प्रतिशत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त हुई। भारत ने जून 2025 में ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया था, जो उसके 2030 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 53 लाख रूफटॉप सौर प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिनसे करीब 63 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। पीएम-कुसुम योजना के तहत लगभग 12 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों और 17 लाख से अधिक ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का सौर ऊर्जीकरण किया गया है। इससे लगभग 16.7 गीगावाट क्षमता जुड़ी है और करीब 30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

उन्होंने ऊर्जा सहयोग, सीमा-पार विद्युत संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिंगापुर, भूटान, IRENA और IEA के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने जुरोंग द्वीप पर सेम्बकॉर्प की 326 मेगावाट-घंटा क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और तुआस क्षेत्र में केपेल के वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र का दौरा भी किया। इस यात्रा से विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भारत की प्रगति साझा करने और ऊर्जा साझेदारियों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

26 अक्टूबर 2026

विद्युत मंत्रालय ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 मनाया; सचिव ने दिलाई सत्यनिष्ठा की शपथ






विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 (26 अक्टूबर से 1 नवंबर) के अवसर पर 26 अक्टूबर 2026 को श्रम शक्ति भवन में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस वर्ष सप्ताह का आयोजन "समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा" विषय के अंतर्गत किया जा रहा है।

विद्युत क्षेत्र के कई संगठनों ने भी इस सप्ताह का आयोजन किया। SJVN ने "समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा" विषय पर ध्यान केंद्रित किया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) ने गुरुग्राम स्थित अपने कॉरपोरेट सेंटर में वॉकाथॉन आयोजित किया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सप्ताह मनाते हुए सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। THDC इंडिया लिमिटेड (THDCIL) ने सत्यनिष्ठा और कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (NPTI) ने भी सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। BEE में यह शपथ उसके कार्यालय में दिलाई गई।






साप्ताहिक सूचना पत्र

24.10.2026 से 30.10.2026

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

24 अक्टूबर 2026

POWERGRID IEC 61850 संस्करण 2.1 सर्वर डिवाइस अनुरूपता परीक्षण मान्यता प्राप्त करने वाली विश्व की पहली यूटिलिटी बनी; 37वाँ स्थापना दिवस मनाया





POWERGRID एडवांस्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (PARTeC) की PAC प्रयोगशाला को IEC 61850 संस्करण 2.1 सर्वर डिवाइस अनुरूपता परीक्षण के लिए UCA इंटरनेशनल यूज़र्स ग्रुप (UCAIug) से मान्यता प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के साथ POWERGRID यह मान्यता हासिल करने वाली विश्व की पहली विद्युत यूटिलिटी बन गई है। यह मान्यता POWERGRID को मानक के अनुरूपता के लिए इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ (IEDs) को प्रमाणित करने में सक्षम बनाती है, जिससे विभिन्न विक्रेताओं के उपकरणों के बीच पारस्परिक संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

POWERGRID ने विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद की उपस्थिति में अपना 37वाँ स्थापना दिवस मनाया। POWERGRID के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) श्री वंशी रामा मोहन बुर्रा ने निदेशक मंडल, सरकार द्वारा नामित निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समारोह का नेतृत्व किया। विद्युत मंत्रालय के सचिव ने कर्मचारियों को बधाई दी और राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण तथा भारत के ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने में POWERGRID की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

29 अक्टूबर 2026

इंडिया एनर्जी स्टैक टास्कफोर्स ने अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की; देशव्यापी क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत



इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) टास्कफोर्स ने 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में बैठक कर अपनी अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की। रिपोर्ट में भारत के विद्युत क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में IES के विस्तार हेतु रणनीति, संरचना, शासन-व्यवस्था और कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें जून 2025 में विद्युत मंत्रालय द्वारा टास्कफोर्स के गठन के बाद से किए गए डिजाइन, विकास और पायलट कार्यान्वयन को समाहित किया गया है।

इंडिया एनर्जी स्टैक खुले मानकों और प्रोटोकॉल का एक साझा समूह है, जो विद्युत वितरण कंपनियों, प्रणाली संचालकों, नियामकों, बाजार प्रतिभागियों, नवाचारकर्ताओं और उपभोक्ताओं को मौजूदा प्रणालियों का संचालन जारी रखते हुए साझा डिजिटल माध्यमों के जरिए सुरक्षित रूप से डेटा का आदान-प्रदान करने और परस्पर संवाद करने में सक्षम बनाता है।

IES को पाँच राज्यों की छह यूटिलिटी—टाटा पावर मुंबई, APEPDCL, DGVCL, PVVNL, BRPL और TPDDL—में पायलट परियोजनाओं के माध्यम से लागू और परीक्षण किया गया है। उपभोक्ताओं ने NeGD के साथ साझेदारी में डिजिलॉकर के माध्यम से उपभोक्ता ऊर्जा पासपोर्ट और उपभोक्ता मीटर डाइजेस्ट सहित सत्यापन योग्य डिजिटल ऊर्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना शुरू कर दिया है। भाग लेने वाली यूटिलिटीज़ के साथ पीयर-टू-पीयर ऊर्जा लेन-देन का प्रदर्शन भी किया गया है और कार्यान्वयन के अगले चरण में सहयोग के लिए खरीद-प्रक्रिया संबंधी रूपरेखा तैयार की गई है।

आगे की दिशा में, टास्कफोर्स ने विद्युत क्षेत्र के हितधारकों को IES के अनुरूप तैयार होने की सिफारिश की है, ताकि पूरे क्षेत्र में परस्पर संचालन योग्य और विस्तार योग्य डिजिटल सेवाओं के लिए एक साझा आधार तैयार हो सके। IES के विनिर्देशों के प्रबंधन और अनुरूपता प्रमाणन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश भी की गई है।

यह पहल विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में नोडल एजेंसी REC लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है, जबकि FSR Global नॉलेज पार्टनर है।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

26 अक्टूबर 2026

REC ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया; AUM में ₹26,537 करोड़ की वृद्धि और नेटवर्थ में साल-दर-साल 14% की बढ़ोतरी दर्ज

REC लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।

प्रमुख प्रदर्शन संबंधी उपलब्धियाँ

* प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों (AUM) में ₹26,537 करोड़ की वृद्धि; 30 सितंबर 2026 को ऋण पुस्तिका ₹6.17 लाख करोड़ रही।
* ₹86,660 करोड़ का नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो, जो साल-दर-साल आधार पर 27% बढ़ा।
* वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में विद्युत क्षेत्र में समकक्ष संस्थानों के बीच सर्वाधिक ₹53,541 करोड़ का वितरण।
* वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में विद्युत क्षेत्र में समकक्ष संस्थानों के बीच सर्वाधिक ₹79,207 करोड़ का वितरण।
* नेटवर्थ में साल-दर-साल आधार पर 14% की वृद्धि।
* SEBI/RBI पायलट परियोजना के अंतर्गत टोकनाइज्ड बॉन्ड जारी करने वाला पहला जारीकर्ता।

वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अधिकतम बिजली मांग ने नया शिखर छुआ, जो विद्युत क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। बिजली की मजबूत मांग, प्रौद्योगिकी-आधारित ऋण आकलन और ग्राहक-केंद्रित समाधानों पर REC के निरंतर ध्यान के परिणामस्वरूप 30 सितंबर 2026 तक ऋण पुस्तिका में क्रमिक आधार पर 5% की वृद्धि हुई और यह ₹6.17 लाख करोड़ तक पहुँच गई।

REC ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के दौरान 3.22% का स्वस्थ शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) बनाए रखा और ₹7,541 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया, जो ₹57.27 की वार्षिकीकृत प्रति शेयर आय (EPS) के बराबर है। नेटवर्थ साल-दर-साल 14% बढ़कर ₹94,325 करोड़ हो गई। प्रति इक्विटी शेयर ₹3.50 का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया गया। शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Net NPA) 0.11% पर पहुँच गई और स्टेज-II परिसंपत्तियों में 80% की कमी होकर वे ₹3,235 करोड़ रह गईं।

नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 27% की साल-दर-साल वृद्धि के साथ ₹86,660 करोड़ हो गया, जबकि गैर-विद्युत अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स पोर्टफोलियो ₹61,637 करोड़ रहा। CRAR 24.04% और CET 1 पूंजी 20.91% रही। तिमाही के दौरान REC को डेटा सेंटर चैंपियन अवॉर्ड 2026 तथा सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बॉन्ड जारीकर्ता और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) जारीकर्ता के लिए सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

30 अक्टूबर 2026

NTPC की सहायक कंपनियों ने BESS और सौर परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की

एनटीपीसी NTPC विद्युत व्यापार Vidyut Vyapar



NTPC की सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN) ने BESS कार्यान्वयन एजेंसी (BIA) के रूप में अपनी पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना के 27 अक्टूबर 2026 को 00:00 बजे से वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की। विद्युत शेड्यूलिंग 28 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई। 250 मेगावाट/500 मेगावाट-घंटा (2 घंटे, 2 चक्र) की इस परियोजना का विकास इंडिग्रिड की विशेष प्रयोजन इकाई (SPV), राजस्थान BESS प्राइवेट लिमिटेड (RBPL) द्वारा निर्माण-स्वामित्व-संचालन (BOO) आधार पर विद्युत मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना के बाजार घटक के प्रथम चरण के अंतर्गत किया गया है। NVVN विद्युत बाजार के माध्यम से बैटरी को चार्ज करेगी और संग्रहित ऊर्जा बाजार में बेचेगी। NTPC की NVVN में 100% हिस्सेदारी है। इस परियोजना का चालू होना भारत के ऊर्जा भंडारण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और देश के ऊर्जा संक्रमण में सहयोग देने की NVVN की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

NTPC की सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) ने राजस्थान के बीकानेर स्थित 250 मेगावाट की कलासर सौर ऊर्जा परियोजना की तीसरी और अंतिम 95.6 मेगावाट क्षमता के 30 अक्टूबर 2026 को 00:00 बजे से वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की। इसके साथ ही परियोजना की पूरी 250 मेगावाट क्षमता वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत आ गई है। परियोजना की वाणिज्यिक क्षमता का अनुबंध रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (REMCL) के साथ है। NTPC की NGEL में 89.01% हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी संस्थागत तथा खुदरा निवेशकों के पास है। इसके साथ NTPC समूह की कुल स्थापित क्षमता 91,668 मेगावाट और वाणिज्यिक क्षमता 90,588 मेगावाट हो गई है।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

29 अक्टूबर 2026

BEE और MSME मंत्रालय ने ADEETIE योजना के क्रियान्वयन को मजबूत करने पर चर्चा की

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय के महानिदेशक ने 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के सचिव के साथ बैठक की। बैठक में उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता (ADEET-IE) योजना के क्रियान्वयन और इसके विस्तार को मजबूत करने पर चर्चा की गई।

बैठक में श्री विनम्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, MoMSME; श्री जिवेश नंदन, IAS, सलाहकार, GIZ; श्री सुनील किसान खंडारे, निदेशक, BEE; श्री पी. श्याम सुंदर, निदेशक, BEE; और श्रीमती अंकिता पांडे, निदेशक, MoMSME उपस्थित रहे।

चर्चा का मुख्य केंद्र MoMSME के संस्थागत नेटवर्क, उद्योग संघों और मौजूदा सहायता तंत्र का उपयोग करके MSME क्लस्टरों में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग को बढ़ाना रहा।
ADEETIE योजना के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए समन्वित जनसंपर्क, तकनीकी सहायता, वित्तपोषण तक बेहतर पहुँच और MSME विकास की मौजूदा पहलों के साथ समन्वय की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

नव राष्ट्र
(28 अक्टूबर, 2026)

स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला प्राधान्यः तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे- मोदी

विकसित भारतासाठी अणुऊर्जेची आवश्यकता

▸ दिल्ली, नवराष्ट्र ब्यूरो. विकसित भारताच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात अणुऊर्जेची आवश्यकता असेल. त्यामुळे देश स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. भारताच्या ५०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर अणुभट्टीने प्रथमच क्रिटिकलिटी प्राप्त करणे ही ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाची उपलब्धी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी संशोधन, नव्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती आणि त्याचा प्रत्यक्ष वापर यांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी नमूद केले.

तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताची नेतृत्वाच्या दिशेने वाटचाल



भारत आज केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा देश राहिलेला नाही, तर स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करून जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अंतराळ संशोधन, औषधनिर्मिती, लस उत्पादन, अणुऊर्जा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारताने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. देशाच्या ऊर्जा गरजा वाढत असताना स्वच्छ आणि विश्वासार्ह ऊर्जास्रोतांचा विकास महत्त्वाचा ठरणार आहे. अणुऊर्जा हा त्यातील एक महत्त्वाचा पर्याय असून, स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या क्षेत्रात क्षमता वाढविण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

तंत्रज्ञानातील संशोधनाचा लाभ सामान्यांना मिळावा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धवाहक तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि दूरसंचार क्षेत्रातील प्रगतीमुळे भारताच्या विकासाला नवी गती मिळत आहे. पाचव्या पिढीच्या दूरसंचार सेवांनंतर आता अधिक प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यावरही भर दिला जात आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील संशोधनाचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, उद्योगांना चालना देणे आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला बळकटी देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. स्वदेशी संशोधन आणि नवोन्मेषाच्या बळावर भारताने जागतिक स्पर्धेत आघाडी मिळवावी, अशी अपेक्षाही मोदी यांनी व्यक्त केली.

दैनिक जागरण
(30 अक्टूबर, 2026)

मंथन



श्रीपद येस्सो नाइक

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री

स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भारत निरंतर अग्रसर है। इस दिशा में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और तमाम चुनौतियों के बावजूद इसे निरंतर विस्तार दिया जा रहा है

जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते तापमान, बदलते मौसम और ऊर्जा असुरक्षा के दोहरे संकट से जूझ रही है, तब भारत ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक ऐसा रास्ता चुना है, जो आने वाले दशकों में उसकी आर्थिक और रणनीतिक ताकत की बुनियाद बन सकता है। पिछले 12 वर्षों में देश का ऊर्जा परिदृश्य जिस तेजी से बदला है, वह सिर्फ बिजली उत्पादन के आंकड़ों में बढ़ोतरी की कहानी नहीं है। यह आत्मनिर्भरता का एक नया सोपान है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर ऊर्जा परिवर्तन की शुरुआत की है। सौर और पवन ऊर्जा का तेज विस्तार, रूफटाप सोलर, पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना, बड़े सोलर पार्क, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन- ये सभी एक ऐसी व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका लक्ष्य केवल कार्बन उत्सर्जन घटाना नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 330 गीगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है। सौर और पवन ऊर्जा इसके सबसे बड़े आधार हैं और कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। भारत को अंदाजा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देश में बिजली की मांग में और तेज वृद्धि होना तय है।

हालांकि भारत की ऊर्जा नीति केवल नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर रहने की नीति नहीं है। देश को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली की जरूरत है। यहां आकर थर्मल पावर और परमाणु ऊर्जा का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन भारत की रणनीति पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा को एक-दूसरे के विकल्प के रूप में देखने के बजाय एक संतुलित ऊर्जा मिश्रण तैयार करने की है। कोयला और परमाणु ऊर्जा से स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, दूसरी तरफ सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार तेजी से किया जा रहा है।

यह दृष्टिकोण भारत के ऊर्जा परिवर्तन को व्यावहारिक बनाता है। क्योंकि केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चुनौती यह भी है कि जब सूरज नहीं निकले या हवा की गति कम हो, तब भी घरों, अस्पतालों, उद्योगों, रेलवे, परिवहन और तेजी से बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली मिलती रहे। इसी वजह से बैटरी एनर्जी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन जैसी तकनीकों पर जोर बढ़ रहा है।

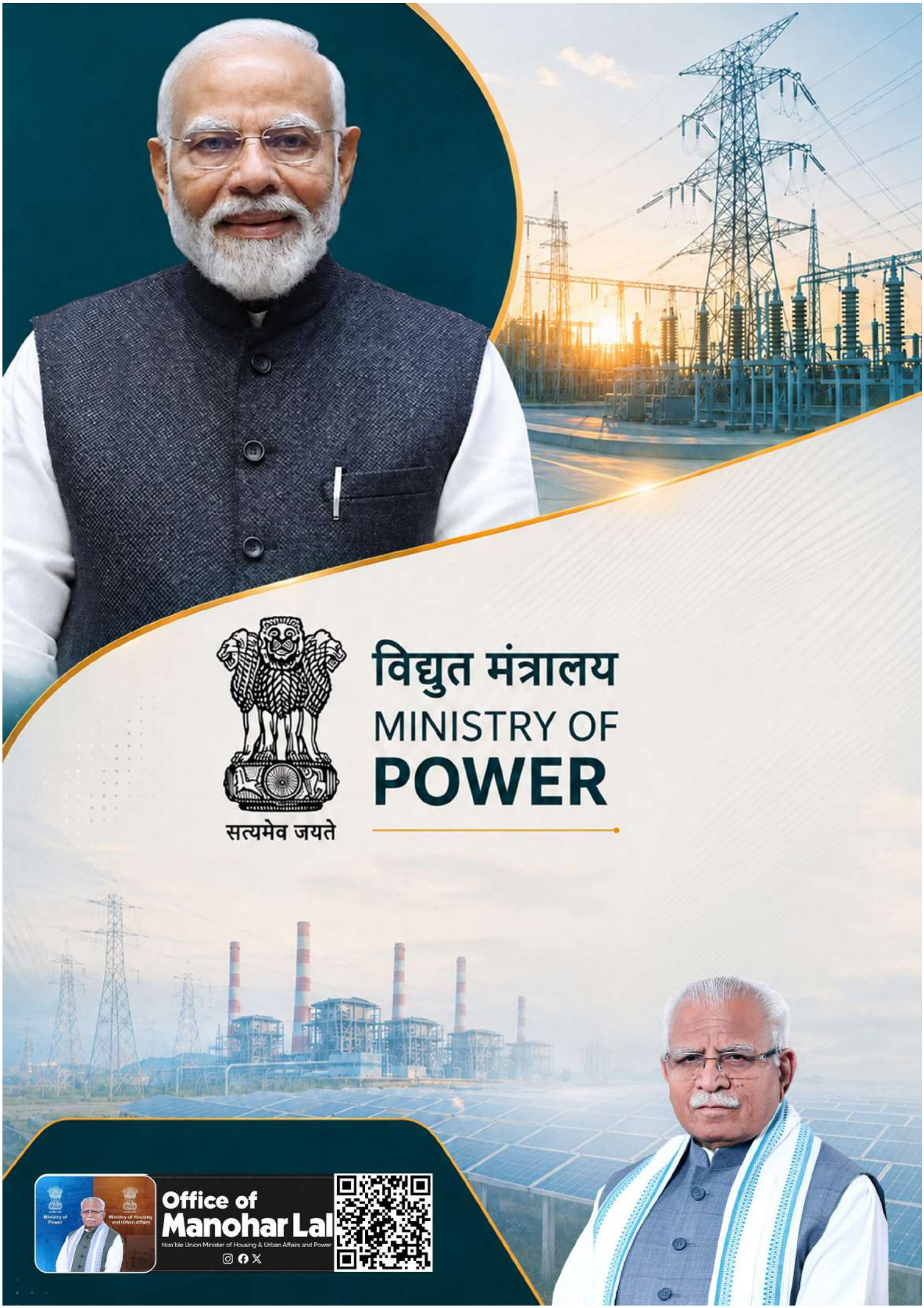
सौलर पंप किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के साथ डीजल पर निर्भरता घटाते हैं। वहीं अनुपयोगी या कम उपयोग वाली जमीन पर सौलर प्लांट लगाने वाले किसान अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय का नया स्रोत तैयार कर सकते हैं। ऊर्जा परिवर्तन किसानों को 'ऊर्जादाता' बनने का भी अवसर दे रहा है। यह बदलाव सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। शहरों में रूफटाप सोलर ने मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बिजली की लागत कम करने का रास्ता खोला है। पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के जरिए घरों की छतों को छोटे ऊर्जा केंद्रों में बदलने की दिशा में काम हो रहा है।

स्टोरेज और ग्रिड की चुनौती : भारत के सामने बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि कितने सौर या पवन ऊर्जा पैदा की जा सकती है। असली चुनौती यह है कि इस ऊर्जा को जरूरत के समय कैसे उपलब्ध कराया जाए। सौर ऊर्जा दिन में अधिक पैदा होती है, जबकि बिजली की मांग निरंतर बनी रहती है। पवन ऊर्जा भी मौसम और हवा की गति पर निर्भर करती है। ऐसे में बैटरी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, एआइ आधारित ग्रिड प्रबंधन और डिजिटल ऊर्जा प्रणालियां भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए निर्णायक साबित होंगी। इसी क्षेत्र में भारत के शोध संस्थान, स्टार्टअप, निजी उद्योग और सरकारी एजेंसियां मिलकर स्वदेशी समाधान विकसित करने की कोशिश कर रही हैं। लक्ष्य साफ है- रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़े, लेकिन बिजली ग्रिड की स्थिरता और किफायतीपन से कोई समझौता न हो।

इस पूरी यात्रा को केवल 'ग्रीन एनर्जी' के चश्मे से देखना शायद इसकी सबसे बड़ी तस्वीर को छोटा कर देगा। इसका सामाजिक असर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गांवों में भरोसेमंद बिजली से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण उद्यमों को गति मिलती है। विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियां स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर पैदा कर सकती हैं। वैसे भी आने वाला दशक उन देशों के लिए निर्णायक होगा, जो आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर सकेंगे। भारत ने इस दौड़ में अपनी दिशा तय कर ली है। चुनौती इस गति को बनाए रखने, भंडारण को मजबूत करने, घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने की है।



स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी तमाम बाधाओं से निपटने में सक्षम दिख रहा भारत। फाइल


सत्यमेव जयते
विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
Office of
Manohar Lal
Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power